भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5992
01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं

5992. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित वर्तमान में संचालित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से लाभान्वित हुए और स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं की संख्या का राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के सुचारू कार्यकरण और इन्हें देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र में लोगों के लिए सुलभ बनाने और सभी लोगों हेतु इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में विज्ञान में अनुसंधान, नवाचार और समावेशी भागीदारी को मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (वाइज़-किरण) जैसी प्रमुख पहलें, वाइज़-पीएचडी, वाइज़-पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप (वाइज़-पीडीएफ), वाइज़-स्कोप, विदुषी और वाइज़-आईपीआर जैसी अध्येतावृत्तियों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती हैं, जो डॉक्टरल से लेकर वरिष्ठ अनुसंधान स्तर तक के करियर में सहायता प्रदान करती हैं। इंस्पायर कार्यक्रम इंस्पायर-मानक और इंस्पायर-एसएचई जैसे घटकों के माध्यम से विद्यालय से लेकर पोस्ट डॉक्टरेट स्तर तक प्रतिभाओं का विकास करता है। नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय नवाचार विकास एवं दोहन पहल (निधि) और प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (टीबीआई) के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें प्रोटोटाइप विकास के लिए युवा और महत्वाकांक्षी नवोन्मेषकों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और गति प्रदान करना (प्रयास) भी शामिल है। एस एंड टी अवसंरचना सुधार कोष (एफआईएसटी) और विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन (पर्स) जैसी योजनाओं के साथ-साथ अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं (एसएआईएफ), अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक एवं तकनीकी सहायता संस्थान (एसएटीएचआई) और मूलभूत अनुसंधान के लिए मेगा सुविधाएं (एमएफबीआर) जैसी सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाता है। राज्य विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (एसएसटीपी), विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल (एसएचआरआई), योग और ध्यान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएटीवाईएएम) और संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल (सीएसआरआई) सहित विषयगत कार्यक्रम क्षेत्र-विशिष्ट और अंतरविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, वहीं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एनसीएसटीसी) के संपर्क प्रयासों ने मध्य प्रदेश में 45 और महाराष्ट्र में 11 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। समता, सशक्तिकरण और विकास के लिए विज्ञान (सीड) प्रभाग के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में आजीविका हेतु स्थानीय नवाचार सुदृढ़ीकरण, स्तरोन्नयन और विकास (सुनील) कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना को सहायता प्रदान की गई, जबकि मध्य प्रदेश में दो परियोजनाओं को महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसटीडब्ल्यू) कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई। राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जैसे राष्ट्रीय मिशनों का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना है, वहीं जैव प्रौद्योगिकी विभाग जैव प्रौद्योगिकी में कैरियर विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और कार्यक्रम (बायो-केयर) संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) उन्नत अनुसंधान अनुदान (एआरजी), प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी), समावेशिता अनुसंधान अनुदान (आईआरजी), त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए भागीदारी (पीएआईआर), राष्ट्रीय पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (एनपीडीएफ) और रामानुजन अध्येतावृत्ति जैसे अनुदानों के माध्यम से व्यापक और केंद्रित आर एंड डी में सहायता करता है, साथ ही राष्ट्रीय विज्ञान चेयर और जेसी बोस अनुदान जैसी प्रतिष्ठित मान्यताएं प्राप्त करने के साथ-साथ, इसने मध्य प्रदेश में 52 और महाराष्ट्र में 117 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, इस प्रकार राष्ट्रव्यापी स्तर पर वैज्ञानिक क्षमता वर्धन और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(ख) से (ग): सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की पहलें क्रियान्वित की हैं, जिनके परिणाम विगत दशक में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। इन योजनाओं ने महिलाओं को उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक यात्रा के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें से कई महिलाओं को अनुसंधान और विकास में अपना करियर फिर से शुरू करने या बनाने में मदद मिली है। विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विज्ञान ज्योति	वाइज़-पीएचडी	वाइज़-पीडीएफ	सीयूआरआईई (क्यूरी)	इंस्पायर-मानक	एसएचई (शी)	इंस्पायर अध्येतावृत्ति	इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति
अंडमान और निकोबार	315	1	0	0	21	0	0	0
आंध्र प्रदेश	2669	0	2	1	5871	1	35	1
अरुणाचल प्रदेश	974	0	1	0	13	0	3	0
असम	3644	11	4	0	177	49	59	1
बिहार	3352	0	0	0	3225	170	6	0
चंडीगढ़	303	4	9	1	168	4	25	0
छत्तीसगढ	3861	2	0	2	4353	522	10	2
दादर, नगर हवेली, दमन और दीव	588	0	0	0	32	1	0	0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विज्ञान ज्योति	वाइज़-पीएचडी	वाइज़-पीडीएफ	सीयूआरआईई (क्यूरी)	इंस्पायर-मानक	एसएचई (शी)	इंस्पायर अध्येतावृत्ति	इंस्पायर संकाय अध्येतावृत्ति
दिल्ली	595	12	33	2	300	75	76	19
गोवा	304	2	3	0	79	4	17	2
गुजरात	4888	6	6	0	1878	95	45	3
हरियाणा	4075	1	1	0	1432	93	23	3
हिमाचल प्रदेश	2704	0	2	1	755	208	23	2
जम्मू और कश्मीर	2425	10	12	0	1506	23	48	4
झारखंड	3569	1	1	0	2474	12	11	3
कर्नाटक	3608	10	12	2	11213	33	103	26
केरल	2790	26	12	7	567	630	86	6
लद्दाख	499	0	0	0	22	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	6	0	0	0
मध्य प्रदेश	4056	9	4	2	2949	834	41	3
महाराष्ट्र	5008	20	17	2	3455	232	86	22
मणिपुर	1220	5	1	0	7	123	3	0
मेघालय	1093	0	0	0	17	42	6	1
मिजोरम	259	2	3	0	13	6	7	0
नागालैंड	301	1	1	0	1	14	2	0
ओडिशा	3662	5	4	1	5691	52	39	2
पुदुचेरी	1195	1	0	0	81	3	5	0
पंजाब	4072	9	14	2	673	105	63	10
राजस्थान	4773	4	1	1	10107	3128	25	2
सिक्किम	454	0	0	0	33	0	4	0
तमिलनाडु	0	21	14	10	2198	24	127	8
तेलंगाना	2415	13	22	2	4596	32	81	6
त्रिपुरा	832	3	0	0	94	1	6	0
उत्तराखंड	2661	8	7	0	2686	486	42	1
उत्तर प्रदेश	6672	10	16	2	7531	7574	87	14
पश्चिम बंगाल	3181	18	25	0	28	333	91	12

निधि-प्रयास योजना से लाभान्वित होने वाली उन महिलाओं की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है, जिन्हें पिछले दस वर्षों में अपना स्टार्टअप/व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिली है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधि-प्रयास लाभार्थियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	23
असम	3
बिहार	5

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निधि-प्रयास लाभार्थियों की संख्या
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	15
गोवा	2
गुजरात	27
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	5
झारखंड	1
कर्नाटक	100
केरल	45
मध्य प्रदेश	7
महाराष्ट्र	66
मणिपुर	1
ओडिशा	25
पंजाब	1
राजस्थान	17
तमिलनाडु	95
तेलंगाना	44
उत्तराखंड	6
उत्तर प्रदेश	24
पश्चिम बंगाल	6

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निधि-प्रयास योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की राज्य-वार और जिला-वार संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य	जिला	निधि-प्रयास लाभार्थियों की संख्या
मध्य प्रदेश	भोपाल	3
	ग्वालियर	2
	इंदौर	1
	उज्जैन	1
महाराष्ट्र	अमरावती	2
	औरंगाबाद	2
	धुले	1
	कोल्हापुर	1
	मुंबई शहर	22
	नागपुर	2
	नासिक	3

राज्य	जिला	निधि-प्रयास लाभार्थियों की संख्या
	पुणे	28
	रायगढ़	2
	सतारा	1
	थाणे	2

(घ) से (ङ): सरकार ने एसटीईएम-संबंधित योजनाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और उन्हें महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश के लोगों तक सुलभ बनाने के लिए कई तरह के सक्रिय और समन्वित उपाय किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य पहुंच बढ़ाना, पारदर्शिता में सुधार करना, मूलभूत ढांचे को मजबूत करना और समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि इन पहलों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। पहुंच और भागीदारी को बढ़ाने के लिए, सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों को अनुसंधान निधि और अवसर प्रदान करके व्यापक आधार पर समावेशन को बढ़ावा दिया है। अल्प सेवित क्षेत्रों में स्थित संस्थानों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। एक हब-एंड-स्पोक मॉडल को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें अग्रणी संस्थान छोटे या ग्रामीण संस्थानों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे उनकी अनुसंधान क्षमता और संसाधनों तक पहुंच में सुधार होता है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। प्रस्तावों को प्रस्तुत करने, उनकी निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करने में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित और उन्नत किए गए हैं, जिससे प्रक्रियाएं अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सुलभ हो गई हैं। इंस्पायर-मानक पोर्टल जैसे प्लेटफार्मों में किए गए सुधारों, जिनमें चैटबॉट सहायता, बेहतर डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन और सरलीकृत नामांकन प्रक्रियाएं शामिल हैं, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और विद्यालयों के लिए बाधाओं को और कम कर दिया है।

सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। एफआईएसटी और पर्स जैसी योजनाओं के माध्यम से, संस्थानों को प्रयोगशालाओं के उन्नयन और आधुनिक उपकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, एसएआईएफ (सैफ) और एसएटीएचआई (साथी) जैसी साझा सुविधाएं स्थापित की गई हैं ताकि उन संस्थानों को उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान की जा सके जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं हैं, जिससे ग्रामीण और छोटे संस्थानों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

क्षमता वर्धन भी क्रियाकलापों का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र रहा है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने, नवाचार-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और अनुसंधान कौशल को मजबूत करने के लिए शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जिनमें इंस्पायरिंग इंडिया इन रिसर्च इनोवेशन एंड एसटीईएम एजुकेशन (आईआरआईएसई) के अंतर्गत पहलें भी शामिल हैं। नवोदित शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन, उद्योग जगत से जुड़ाव और कौशल विकास के अवसरों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे वे वैज्ञानिक प्रगति में प्रभावी तौर पर योगदान दे सकें। जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए जनसंपर्क और सहभागिता संबंधी गतिविधियों का विस्तार किया गया है। छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें वास्तविक दुनिया में एसटीईएम अनुप्रयोगों से परिचित कराने के लिए विज्ञान प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, मार्गदर्शन कार्यक्रमों और संस्थागत दौरों का आयोजन किया गया है।

अब तक, इन कदमों के परिणामस्वरूप ग्रामीण संस्थानों की भागीदारी में सुधार हुआ है, योजना कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता आई है, मूलभूत ढांचे और अनुसंधान क्षमता में वृद्धि हुई है, और मार्गदर्शन और शिक्षण संसाधनों तक पहुंच बढ़ी है। इन उपायों के संयोजन से एक अधिक समावेशी और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश के लोगों के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और उनके लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करता है।

*****